

मानव विकास के विविध आयाम बिहार राज्य के विशेष संदर्भ में

प्रत्यूष चंद्र मिश्रा

अर्थशास्त्र विभाग मगध विश्वविद्यालय बोधगया।

ARTICLE DETAILS

Article History

Published Online: 15 April 2019

Keywords

मानवीय विकास, सामाजिक भागीदारी, संयुक्त राष्ट्र

ABSTRACT

मानवीय विकास की विचारधारा डॉ. महबूब उल हक द्वारा प्रस्तावित की गई थी। उनके मुताबिक मानवीय विकास वो विकास है जो लोगों के समक्ष विकल्प बढ़ाए और उनका जीवन बेहतर बनाए अतः, सब विकास लोगों के आस पास ही घूमता है। विकल्प कभी स्थायी नहीं रहते हमेशा बदलते रहते हैं। विकास का मूल उद्देश्य है जहां लोगों को सार्थक जीवन जीने के लिए परिस्थितियां बनाई जाए जीवन का कुछ उद्देश्य जरूर होना चाहिए, इसका मतलब लोग स्वस्थ होना चाहिए, अपने हुनर को निखार सकें, सामाजिक भागीदारी और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की छूट एक लम्बा और स्वस्थ जीवन, ज्ञान हासिल करने के लिए सक्षम होना और एक सभ्य जीवन जीने के लिए पर्याप्त साधन होना मानव विकास के बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं। इसीलिए, संसाधनों का उपयोग, स्वस्थ और शिक्षा मानव विकास में महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास के प्रत्येक कार्यक्रम के अन्तर्गत इस समय पूरी दुनिया में भारत और चीन की जनसंख्या को लेकर बहुत चर्चा रहती है। यही बजह है कि दुनिया के अन्य देश भी अपनी आबादी को विकास की कसौटी पर माप और तोल रहे हैं। दुनिया की आबादी को लेकर पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट 'वल्ड पापुलेशन प्रास्पेक्ट्स' की एक रिवीजन रिपोर्ट प्रकाशित हुयी है। इसमें साफ कहा गया है कि है आज दुनिया की आबादी जो तकरीबन 7.5 अरब है वह 2030 तक 9.7 अरब और उसके 2050 तक उसके 11.2 अरब होने की उम्मीद है। भारत और चीन के बारे में यह रिपोर्ट खुलासा करती है कि आज चीन की आबादी दुनिया की 19 फीसदी और भारत की 18 फीसदी है। अनुमान है कि 2028 तक भारत चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जायेगा। तब इन दोनों देशों की अपनी-अपनी आबादी 1.5 अरब को पार कर जायेगी। इसके बाद भी भारत की आबादी बढ़ना जारी रहेगी तथा चीन की आबादी में गिरावट की सम्भावनायें प्रबल होंगी। रिपोर्ट यह भी साफ करती है कि विकसित देशों की आज जो आबादी 1.5 अरब है, इसमें तो कोई खास बदलाव नहीं होगा। परन्तु इसके विपरीत 49 अल्प विकसित देशों की अभी जो आबादी एक अरब के आस-पास है, वह 2050 तक बढ़कर दो अरब जरूर हो जायेगी। आज विश्व की इस बढ़ती जनसंख्या के साथ ही भारत में अहम् सवाल यह है कि क्या इस बढ़ती हुई आबादी को हम केवल संसाधनों का रोना रोकर केवल कोसते रहें अथवा इसके मुकाबले हम अपनी आबादी को श्रेष्ठ मानव संसाधन के रूप में विकसित करते हुए ऐसे कौशल से युक्त बनायें।

प्रस्तावना

मानव विकास सूचकांक (HDI) जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, और आय सूचकांकों का एक संयुक्त सांख्यिकी सूचकांक है जिसे मानव विकास के तीन आधारों द्वारा तैयार किया जाता है। इसे अर्थशास्त्री महबूब-उल-हक द्वारा बनाया गया था, जिसका 1990 में अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन द्वारा समर्थन किया गया, और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा प्रकाशित किया गया। UNDP ने मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए एक नई विधि की शुरुआत की है। निम्नलिखित तीन सूचकांक इस्तेमाल किये जा रहे हैं:

1. जीवन प्रत्याशा सूचकांक (लम्बा व स्वस्थ जीवन)
2. शिक्षा सूचकांक (शिक्षा का स्तर)
3. आय सूचकांक (जीवन स्तर)

किसी देश के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक उत्थान में, उस देश में उपलब्ध मानव संसाधन अथवा आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मानव शक्ति का आकार तथा उसका गुणात्मक स्वरूप देश के विकास की दिशा, एवं विकास के पथ को

निर्धारित करती है। मानव ही उत्पादन का साधन बन कर आर्थिक विकास को गति प्रदान करता है। 1990 में सर्वप्रथम प्रकाशित मानव विकास प्रतिवेदन ने मानव विकास को, लोगों के सामने, विकल्प के विस्तार की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। इनमें अधिक महत्वपूर्ण है विस्तृत और स्वस्थ जीवन, शिक्षा प्राप्ति और अच्छा जीवन स्तर को पाना। अन्य विकल्प हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता, मानवाधिकारों का आश्वासन और आत्म-सम्मान के विविध तत्वा ये सभी जरूरी विकल्प हैं जिनके अभाव में दूसरों अवसरों में बाधा पड़ती है। अतः मानव विकास, लोगों के विकल्पों में विस्तार के साथ-साथ प्राप्त होने वाले कल्याण के स्तर को ऊंचा करने की प्रक्रिया है। पॉल स्ट्रीटन ने ठीक ही लिखा है कि मानव विकास की संकल्पना, मानव को कई दशकों के अंतराल के बाद पुनः केन्द्रीय मंच पर प्रस्थापित करती है। इन बीते दशकों में तकनीकी संकल्पनाओं की भूल-भुलैया में यह बुनियादी दृष्टि अस्पष्ट बनी है।

मानव विकास उद्देश्य

- सामाजिक नीति, कार्यक्रम व सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक एकीकृत उपागम को अपनाना व क्रियान्वित करना,
- मानव विकास व सामाजिक विकास में उन्नति के लिए राष्ट्रीय स्तर की क्षमताओं का निर्माण करना,
- मानव विकास से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के नेटवर्क व साझेदारियों को विकसित करना व सशक्त बनाना,
- सामाजिक व मानव विकास से संबंधित कार्यक्रमों व सेवाओं को बेहतर बनाना व उनमें सामन्जस्य स्थापित करना,
- बेहतर मानव-विकास के लिए ज्ञान व उपागमों को सुदृढ़ बनाना,
- प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च स्तर पर शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था करना,
- प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना तथा उसकी समुचित व्यवस्था करना,
- कार्य-प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, तथा
- ऐसी स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करना जो लोगों की जीवन-प्रत्याशा, शक्ति, उत्साह तथा कार्यक्षमता में वृद्धि कर सकें।

मानव विकास रिपोर्ट के विषय

वर्ष 1990 : मानव विकास की अवधारणा एवं मापन ।

वर्ष 1995 : लिंग एवं मानव विकास ।

वर्ष 1999 : मानवीय चेहरे के साथ भूमंडलीकरण ।

वर्ष 2000 : मानवाधिकार एवं मानव विकास ।

वर्ष 2003 : सहस्राब्दि विकास लक्ष्य : मानव निर्धनता की समाप्ति हेतु देशों के मध्य समझौता ।

वर्ष 2010 : राष्ट्रों का वास्तविक धन : मानव विकास के मार्ग ।

वर्ष 2013 : दक्षिण का उदय : विविधतापूर्ण विश्व में मानव प्रगति ।

मानव विकास के स्तंभ

मानव विकास के चार स्तंभ हैं:

- **निष्पक्षता** - मतलब उपलब्ध अवसरों को बिना पक्षपात के सभी लोगो तक पहुंचाना, और वह अवसर बिना किसी लिंग, जाती, और आय भेदभाव के उपलब्ध होना चाहिए ।

- **स्थिरता** - अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता को दर्शाता है । सतत मानव विकास करवाने के लिए, हर पीढ़ी को समान अवसर होना चाहिए । सभी पर्यावरण वित्तीय और मानव संसाधन भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्रयोग किए जाने चाहिए । इन संसाधनों में से किसी के भी दुरुपयोग से भविष्य की पीढ़ियों को कम अवसर मिलेंगे ।
- **उत्पादकता** - मानव श्रम उत्पादकता या मानव काम के लिहाज से है कि लगातार लोगों में क्षमताओं के निर्माण से समृद्ध किए जाने को दर्शाता है । अंत में, यह लोग हैं, जो राष्ट्र की वास्तविक संपत्ति है । इसलिए, उनके ज्ञान को बढ़ाने के प्रयासों, या बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं अंततः बेहतर कार्य कुशलता के लिए योगदान करेंगी ।
- **अधिकारिता** - स्वतंत्रता और क्षमता में वृद्धि से ही उनकी विकल्प चुनने की क्षमता बढ़ती है और अधिकारिता आती है । सुशासन और उन्मुख नीतियां लोगों को सशक्त करने के लिए आवश्यक हैं । सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों के सशक्तिकरण के लिए विशेष महत्व का है ।

मानव विकास का महत्व

किसी देश का आर्थिक विकास उस देश में उपलब्ध मानव पूँजी के स्टॉक तथा संचय की दर पर निर्भर करता है। विकासशील देशों में नियोजित आर्थिक विकास की प्रक्रिया में मानव के विकास पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता। यही कारण है कि इन देशों में विकास के वांछित लक्ष्य नहीं प्राप्त हो पाते हैं तथा वहाँ विकास की दर निम्न रहती है। आज अधिकांश विकासवादी अर्थशास्त्री इस बात के पक्षधर हैं कि मानव-पूँजी में अधिक से अधिक विनियोग किया जाना चाहिए ताकि आर्थिक विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक मानव संसाधन का समुचित विकास किया जा सके। किसी भी देश की जनसंख्या का जितना अधिक हिस्सा शिक्षित, कुशल एवं प्रशिक्षित, होकर रोजगार में लगा हुआ है, वह देश उतना ही तेजी से विकास करेगा। आर्थिक विकास की दृष्टि से भौतिक पूँजी की अपेक्षा मानव पूँजी को कहीं अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है क्योंकि मानवीय साधनों की कुशलता एवं दक्षता पर ही आर्थिक विकास का ढांचा खड़ा किया जा सकता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मार्शल का भी विचार था कि “सबसे मूल्यवान पूँजी वह है जो मानव-मात्र में विनियोजित की जाये।”

बिहार में मानव विकास के प्रारूप

मौजूदा दौर में अगर “बहुप्रचारित विकसित बिहार” की बात करें तो लंबी-चौड़ी सड़कों, अपार्टमेंट्स एवं मॉल्स के निर्माण और विकास दर

(आंकड़ों की बाजीगरी) के बढ़ने को ही विकास बताया जा रहा है। विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों की समझ के साथ विकास के प्रारूप के निर्माण, समस्याओं के समाधान, सत्ता की पारदर्शिता और विकेन्द्रीकरण के बिना सम्यक विकास सम्भव ही नहीं है। भौगोलिक दशा और दिशा को ध्यान में रखकर विकास के विविध प्रारूपों के नियोजन और क्रियान्वयन से ही समग्र विकास का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। विकास के एक कॉमन मॉडल से सिर्फ विसंगतियां और विरोधाभास उत्पन्न होंगे। मसलन उत्तरी बिहार की भौगोलिक स्थिति दक्षिणी बिहार के ठीक विपरीत है, प्राकृतिक संरचनाएं व संसाधन भिन्न हैं, भौतिक व मानवीय संसाधन भिन्न हैं तो प्रारूप भी भिन्न होना चाहिए। मानव विकास के साथ जुड़ा एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण पहलू (परजीवी) है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार से विकास की नीति और सरोकार दोनों प्रभावित होते हैं। मानव विकास के हरेक स्तर को प्रभावित करता है भ्रष्टाचार। यह त्रासदी है जो ना तो समाज की फ़िक्र करता है ना ही इससे जुड़ी संरचनाओं की। इसकी प्रवृत्ति सदैव ही मानव विरोधी रही। बिहार में भ्रष्टाचार अपने विभिन्न अवतारों में व्यापकता के साथ विद्यमान है और अर्थसत्ता को सर्वोपरि बनाकर राजसत्ता का उपयोग कर रहा है। इस के कारण विकास का भ्रामक, एकांगी एवं प्रदूषित प्रारूप पूर्व में भी ऊभर कर आता रहा है और वर्तमान में भी आ रहा है। भ्रष्टाचार की नकेल कसे बिना विकास के किसी भी प्रारूप की सार्थकता साबित नहीं जा सकती है।

बिहार सरकार, मानव विकास के खास आयामों को सार्थक मुकाम देने में जुटी है। स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, समाज कल्याण, महिला सशक्तीकरण, वृद्ध व दिव्यांगों की सुरक्षा को लेकर किए गए, किए जा रहे कार्यों का असर दिख भी रहा है। 7 साल में बिहार में हर आदमी पर विकास का खर्च 15.8 फीसदी की दर से बढ़ा, जबकि देश के लिए यह दर सिर्फ 13.7 फीसदी रही। 2011-12 से 10.9 प्रतिशत का स्थिर विकास दर, अर्थव्यवस्था के टिकाऊ व समावेशी विकास वाली स्थिति की भी गवाही है।

स्वास्थ्य, शिक्षा पर खर्च : पिछले 7 वर्ष में स्वास्थ्य पर खर्च की वार्षिक वृद्धि दर 22 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रही। शिक्षा पर खर्च 14.4 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़कर किया गया।

जन्मकालीन संभाव्यता बढ़ी : स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में हुए काम का असर जन्मकालीन जीवन संभाव्यता, शिशु मृत्यु दर व माता मृत्यु दर पर पड़ा। यह सुधरा। पिछले छह वर्ष में जन्मकालीन संभाव्यता 2.9 वर्षों की वृद्धि के साथ 68.7 वर्ष पहुंची। यह देश की जन्मकालीन संभाव्यता के बराबर है।

30 बेड के होंगे पीएचसी : 533 में से 399 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को 6 बेड से 30 बेड वाला किया जाएगा। 70 रेफरल अस्पतालों में से 67 में ओपीडी व आईपीडी, दोनों है। 55 अनुमंडलीय अस्पतालों में 46 चालू हैं। 9 खुलने हैं। संस्थागत प्रसव की संख्या 2011-12 में 14.07 लाख से बढ़कर 2017-18 में 16.37 लाख हुई।

पेयजल, स्वच्छता : यह बुनियादी मकसद, 7 निश्चय योजना के तहत साधा जा रहा है।

स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या अब 1 फीसदी से भी कम 42 हजार 825 प्राथमिक विद्यालय तथा 30 हजार 156 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। 6 से 14 वर्ष उम्र के बीच पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों को विद्यालय में वापस लाने में खासी प्रगति हुई। अब ऐसे बच्चों की संख्या 1 प्रतिशत से भी कम हुई है।

अक्षर आंचल : 15 से 35 वर्ष तक की 8 लाख महादलित और अति पिछड़ा वर्ग की महिलाएं तथा 4 लाख अल्पसंख्यक महिलाओं को बुनियादी शिक्षा तथा विकासमूलक कार्यक्रमों के जरिए मुख्य धारा में लाने के लिए अक्षर आंचल योजना जारी है। उच्च शिक्षा : अभी 24 विश्वविद्यालय हैं। 15 शोध संस्थान हैं। 2017 में 277 राजकीय महाविद्यालय व 496 स्थानीय निकाय महाविद्यालय थे। 87 महाविद्यालयों और 7 विश्वविद्यालयों को नैक की मान्यता है।

भारत का मानव विकास सूचकांक

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की अद्यतन रिपोर्ट में भारत का मानव विकास सूचकांक 188 देशों में पांच पायदान की छलांग के साथ 130वें स्थान पर है। वर्ष 2014 में भारत इस सूचकांक के लिए 0.609 अंक मिला। 1980 से लेकर 2014 के बीच भारत का मानव विकास सूचकांक 0.326 से बढ़कर 0.609 हो गया। यह 68.1 फीसदी की वृद्धि है। सालाना दर पर यह 1.54 फीसदी की वृद्धि है। मानव विकास सूचकांक तीन मुख्य आयामों पर आधारित है, इनमें आयु एवं स्वास्थ्य जीवन, ज्ञान के लिए पहुंच और जीवन स्तर शामिल हैं। भारत को असमानता, विशेषतकर शिक्षा में असमानता 42.1 प्रतिशत के कारण 28.6 प्रतिशत एचडीआई का नुकसान हुआ है। ब्रिक्स देशों में असमानता के चलते दक्षिण अफ्रीका को सर्वाधिक - 35.7 प्रतिशत और रूस को सबसे कम 10.5 प्रतिशत नुकसान है। 155 देशों के लैंगिक असमानता सूचकांक (जो लिंग आधारित असमानता तीन आयामों, प्रसूता स्वास्थ्य, सशक्तीकरण और आर्थिक गतिविधि, में दर्शाता है) में भारत का स्थान 0.563 अंक के साथ 130वां है। इथियोपिया में आज जारी 2015 वैश्विक

मानव विकास रिपोर्ट में सरकारों से अब यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि कार्य जनता की बेहतरी , असमानता दूर करने, आजीविका

हासिल करने और लोगों को सशक्त बनाने में योगदान कर सकें।

| क्रम. | मानव विकास सूचकांक | मानव विकास के मामले में देशों की स्थिति |
|-------|--------------------|---|
| 1 | 0 से .550 से कम | निम्न मानव विकास वाले देश |
| 2 | .550 से .700 से कम | मध्यम मानव विकास वाले देश |
| 3 | .700 से .800 से कम | उच्च मानव विकास वाले देश |
| 4 | .800 से 1 | बहुत उच्च मानव विकास वाले देश |

ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) के बीच भारत का मानव विकास सूचकांक मूल्य सबसे कम है. सूचकांक के अनुसार भारत जीवन प्रत्याशा को छोड़कर मानव विकास सूचकांक की सभी कसौटियों में अन्य ब्रिक्स देशों की तुलना में सबसे नीचे है. एचआईवी-एड्स के कारण ब्रिक्स देशों के बीच दक्षिण अफ्रीका में जीवन प्रत्याशा कम है. ब्रिक्स देशों में रूस, ब्राजील और चीन उच्च मानव विकास सूचकांक वर्ग में क्रमशः 57वें, 79वें और 91वें स्थान पर हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका और भारत क्रमशः 118वें और 135वें स्थान के साथ मध्यम वर्ग में है. मानव विकास सूचकांक किसी देश के मानव जीवन के तीन मुख्य आयामों में दीर्घकालिक प्रगति की रिपोर्ट होता है. इसमें दीर्घ स्वस्थ जीवन, शिक्षा सुविधा और अच्छा जीवन स्तर शामिल हैं. 2013 के इस अध्ययन में 2012 और 2011 की ही तरह 187 देश शामिल किए गए थे.

15 नवंबर 2013 तक एक वर्ष में कुछ देशों की स्थिति में परिवर्तन हुआ है. रिपोर्ट में 1980 से 2013 के बीच भारत की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा गया है कि भारत का सूचकांक 0.614 के स्तर से कम (0.586) पर रहा जो दक्षिण एशिया के औसत सूचकांक (0.588) से भी कम है. भारत के पड़ोसी बांग्लादेश और पाकिस्तान क्रमशः 142वें और 146वें स्थान पर हैं, जबकि नेपाल 145वें स्थान पर है. स्त्री-पुरुष के बीच असमानता संबंधी सूचकांक के दृष्टिकोण से भारत 152 देशों में 127वें स्थान पर रहा. भारत में 10.9 प्रतिशत सांसद महिलाएं हैं और 26.6 प्रतिशत वयस्क महिलाएं माध्यमिक शिक्षा प्राप्त हैं जबकि इस स्तर की शिक्षा प्राप्त करने वाले पुरुषों का अनुपात 50.4 प्रतिशत है. भारत में श्रम बाजार में स्त्रियों की भागीदारी 28.8 प्रतिशत है जबकि पुरुषों की हिस्सेदारी 80.9 प्रतिशत है. बहुआयामी गरीबी के सूचकांक के अनुसार भारत की 55.3 प्रतिशत आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है जबकि

18.2 प्रतिशत लोग बहुआयामी गरीबी के आस-पास हैं. बहुआयामी गरीबी किसी परिवार में शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, इन विविध आयामों की दृष्टि से विपन्नता का सूचक है.

सारांश

मानव जीव एक जटिल तंत्र है जिसमें शारीरिक ऊर्जा तथा मानसिक ऊर्जा दोनों ही होते हैं। शारीरिक ऊर्जा से व्यक्ति शारीरिक क्रियायें जैसे- दौड़ना, सांस लेना, लिखना आदि क्रियायें करता है तथा मानसिक ऊर्जा से व्यक्ति मानसिक कार्य जैसे-स्मरण, प्रत्यक्ष चिन्तन आदि करता है। इन दोनों तरह की ऊर्जाओं का स्पर्श बिन्दू उपाहं होता है। इन ऊर्जाओं से सम्बन्धित कुछ ऐसे संप्रत्यय का विकास की जरूरत है जिनसे व्यक्तित्व के गत्यात्मक पहलुओं जैसे- मूलप्रवृत्ति, चिन्ता तथा मनोरचनाओं का वर्णन होता है। मानव विकास के लिए ये जरूरी है की सरकारों को नौकरियों से आगे बढ़ कर अवैतनिक देखभाल करनी चाहिये , स्वैच्छिक या सृजनात्मक कार्य जैसे विभिन्न प्रकार के मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्यों पर विचार करने को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। अनुकूल परिस्थितियां और कार्य की अच्छी गुणवत्ता मानव विकास में पर्याप्त रूप से योगदान कर सकती है। हालांकि बंधुआ मजदूरी, बाल मजदूरी और मानव तस्करी के रूप में कार्य मानवाधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं और घरेलू नौकर, यौन व्यापार या खतरनाक उद्योगों में कार्य जैसे कुछ कार्य कामगारों को जोखिम में डाल सकते हैं। मानव विकास की अवधारणा मानवीय विकास से संबंधित है जिसका मुख्य उद्देश्य किसी भी राष्ट्र से जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पक्षों को प्रभावित करना है। चूँकि मानवीय विकास एक बृहद् अवधारणा है अतः इसके अंतर्गत समाज के विभिन्न वर्गों व उनसे संबंधित मुद्दों को ध्यान में रखते हुए नीतियों एवं कार्यक्रमों का निर्माण किया जाना चाहिये।

संदर्भ सूची

1. नई दिल्ली संयुक्त राष्ट्र विकास मानव विकास सूचकांक New Delhi UN Development Human Development Index
2. मानव संसाधन को विकसित करने में अग्रणी Vol 6 (# 3) अगस्त 2004 और Vol 8, # 3, 2006
3. केली डी, 2001, मानव संसाधन विकास की दोहरी धारणाएं: नीति के मुद्दे: SME, अन्य क्षेत्र और मानव संसाधन विकास की विवादित परिभाषाएं, <http://ro.uow.edu.au/artspapers/26>
4. मैक्लीन, G.N., उस्मान-गनी, A.M., & Cho, (Eds.). राष्ट्रीय नीति के रूप में मानव संसाधन विकास. मानव संसाधन के विकास में अग्रणी, अगस्त (2004) 6(3).
5. मानव संसाधन विकास की और बढ़ता रुझान, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा पत्रिका Vol 12, No. 2, p7